

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 565]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 अक्टूबर 2017—आश्विन 24, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2017

क्र. 16504-226-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ५ सन् २०१७.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, २०१७

[“मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक १६ अक्टूबर, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक १७ सन् १९६१ का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (क-दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(क-दो) “प्रशासक से अभिप्रेत है, तृतीय श्रेणी कार्यपालक से अनिम्न श्रेणी का कोई शासकीय सेवक अथवा सोसाइटी अथवा उसी वर्ग की सोसाइटी के संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सोसाइटी के कारबार के संचालन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया हो जो रजिस्ट्रार के नियंत्रण तथा मार्गदर्शन के अधीन कार्य करेगा;”.

भोपाल :

तारीख ११ अक्टूबर, २०१७

ओ. पी. कोहली

राज्यपाल

मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2017

क्र. 226-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 5 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 5 OF 2017

**THE MADHYA PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2017**

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 16th October, 2017.]

Promulgated by the Governor in the sixty-eighth year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2017. Short title and commencement.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in Madhya Pradesh Gazette.
2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendment specified in sections 3. Madhya Pradesh Act No. 17 of 1961 to be temporarily amended.
3. In section 2 of the principal Act, for clause (a-ii), the following clause shall be substituted, namely :— Amendment of Section 2.

"(a-ii) "Administrator" means any Government Servant, not below the rank of class III executive or any person eligible for election as a member of the Board or Directors of society or same class of society, who has been appointed as Administrator by the Registrar under the provisions of this Act, to conduct the business of the society and who shall work under the control and guidance of the Registrar;"

BHOPAL :
Dated, the 11th October, 2017.

O. P. KOHLI
Governor
Madhya Pradesh.